सोना 40 रुपए टूटा, चांदी 60 रुपए सस्ती

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। आभूषण निर्माताओं की ओर से मांग कमजोर पडऩे से आज दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 40 रुपए लुढ़ककर 33,030 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। चांदी भी 60 रुपए की गिरावट के साथ 40,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। गत दिवस स्थानीय बाजार में सोना पहली बार 33 हजार के पार पहुंचा था। आभूषण निर्माता इस स्तर पर खरीद करने से आज बचते दिखे। इससे पीली धातु में मामूली गिरावट देखी गई। कारोबारियों का कहना है कि सोने को विदेशी बाजार से समर्थन मिल रहा है और इसलिए आगे इसमें तेजी लौट सकती है। विदेशों में शुक्रवार को सोना हाजिर 4.05 डॉलर की बढ़त में 1,292.15 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। फरवरी का अमेरिकी सोना वायदा आठ डॉलर की मजबूती के साथ 1,295.40 डॉलर प्रति औंस बोल गया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका में आर्थिक सुस्ती के मद्देनजर फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि का क्रम टूट सकता है। इसे डॉलर पर दबाव आया है तथा पीली धातु को बल मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर भी 0.12 डॉलर की बढ़त में 15.68 डॉलर प्रति औंस पर रही।

ब्रिटेन में पांच हजार लोगों को नौकरी से निकाल सकती है जगुआर लैंड रोवर :: रिपोर्ट

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। लग्जरी वाहन बनाने वाली कंपनी जगुआर लैंड रोवर बृहस्पतिवार को पांच हजार लोगों तक की छंटनी की घोषणा कर सकती है। बीबीसी ने इसकी जानकारी दी है। कंपनी चीन में बिक्री कम होने तथा ब्रेक्जिट से जुड़ी आशंकाओं के मद्देनजर यह कदम उठाने वाली है। टाटा मोटर्स की स्वामित्व वाली इस कंपनी में ब्रिटेन में 40 हजार से अधिक लोग काम करते हैं। हालांकि, कंपनी से इस बारे में कोई बयान नहीं मिल सका है। बीबीसी की खबर के अनुसार, इस छंटनी का सर्वाधिक असर विपणन, प्रबंधन तथा संचालन से संबंधित कर्मचारियों पर होगा। बीबीसी ने कहा कि यह छंटनी 3.20 अरब डॉलर की बचत करने की योजना का हिस्सा है।

खबर में कहा गया है कि कंपनी चीन में बिक्री में गिरावट तथा यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने के कारण ऐसा कर रही है। कंपनी ब्रेक्जिट के बाद भी यूरोपीय संघ में अपना संयंत्र सुनिश्चित करने के लिये पहल कर चुकी है। ब्रिटेन 29 मार्च को समूह से बाहर हो रहा है। कंपनी पश्चिमी स्लोवाकिया के नित्रा में अक्टूबर में 1.60 अरब डॉलर का संयंत्र शुरू कर चुकी है।

निसान के पूर्व चेयरमैन पर लगा विश्वासघात का आरोप

तोक्यो, 11 जनवरी (ए)। निसान के पूर्व चेयरमैन कार्लोस घोसन पर तोक्यो की एक जिला अदालत में शुक्रवार को विश्वासघात का आरोप लगा। एक समय के दिग्गज कारोबारी के लिए यह ताजा झटका है।

घोसन को 19 नवंबर को हिरासत में लिया गया था।इससे पहले उन पर वित्तीय रिपोर्ट में अपनी आय को कम करके बताने का आरोप लगा था। घोसन, निसान के एक और कार्यकारी ग्रेग केली एवं निसान पर शुक्रवार को वित्त वर्ष 2015 से 2017 के बीच आय को कम करके बताने का एक और आरोप लगा। घोसन के अधिवक्ता ने कहा कि वह अपने मुवक्किल की जमानत का अनुरोध करेंगे। विश्वासघात के आरोप में घोसन की हिरासत अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। हालांकि केली और निसान पर विश्वासघात के आरोप नहीं लगे हैं।

टीसीएस ने डेनियल ह्यूजेस कैलहन को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया

नयी दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डेनियल ह्यूजेस कैलहन को कंपनी का अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। टीसीएस ने बयान जारी कर कहा है कि कैलहन को पांच साल के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 10 जनवरी, 2019 से प्रभावी है। कंपनी ने कहा है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर कैलहन की नियुक्ति हुई है और शेयरधारकों को इसकी मंजूरी देनी है। टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, डॉन कैलहन को हमारे बोर्ड में शामिल किया जाना, मेरे लिए हर्ष का विषय है। वित्तीय सेवा उद्योग और वैश्विक प्रौद्योगिकी और कारोबार संचालन में डॉन के व्यापक अनुभव से टीसीएस को फायदा होगा। कैलहन नवंबर, 2018 तक सिटीग्रुप के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और परिचालन प्रमुख थे। इसके अलावा वह सिटी की परिचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। वर्ष 2007 में सिटी समूह से जुड़ने से पहले वह आईबीएम जापान, मॉर्गन स्टेनली और क्रेडिट सुईस जैसी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुके थे।

किसानों-गरीबों को मिलेगा तोहफा खाते में आएंगे 30 हजार रुपए

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के बाद मोदी सरकार अब किसानों, बेरोजगारों और गरीबों के लिए जल्द ही खजाना खोलने जा रही है। केंद्र सरकार, अगली कैबिनेट बैठक में इस बात का ऐलान कर सकती है। यह बैठक मकर संक्रांति के ठीक एक दिन बाद 16 जनवरी को होगी।

खाते में एकमुश्त ट्रांसफर होगी रकम

कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार सभी तरह के किसानों, बेरोजगारों और गरीब लोगों को एक मुश्त 30 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस मदद को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम (यूबीआई) के तहत दिया जाएगा। हालांकि इस स्कीम के लागू होने के बाद लोगों को राशन और एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इसमें वो किसान भी शामिल होंगे, जो दूसरों के यहां मजदूरी करते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को खेती के लिए अब सरकार सीधे खाते में पैसे देगी। खास बात यह है कि जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं है, सरकार उन्हें भी इस स्कीम में शामिल करके फायदा पहुंचाएगी।

प्रत्येक महीने मिलेगी इतनी रकम

मोदी सरकार के प्लान के मुताबिक गरीब किसानों व बेरोजगारों को प्रत्येक महीना 2500 हजार रुपया दिया जाएगा। यह राशि हर महीने के बजाए एकमुश्त दी जाएगी। किसान के परिवार को भी मदद पहुंचाई जा सकती है। राहत पैकेज में बीमा, कृषि लोन, आर्थिक मदद दी जा सकती है। स्कीम में छोटे, सीमांत और बटाईदारों या किराया पर किसानी करने वाले किसानों को फायदा देने पर जोर है।

क्या है मोदी सरकार की स्कीम

किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने जिन दो मॉडल का अध्ययन किया है उसमें ओडिशा का मॉडल ज्यादा दमदार है। ओडिशा के कालिया मॉडल में किसानों को 5 क्रॉप सीजन में 25000 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, मोदी सरकार किसान को सालाना एक मुश्त आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है।

क्या है यूबीआई

संसद में वर्ष 2017-17 के लिए पेश आर्थिक सर्वेक्षण में इसका जिक्र किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था कि यूबीआई एक बेहद शक्तिशाली विचार है और यदि यह समय इसे लागू करने के लिए परिपक्व नहीं है तो इस पर गंभीर चर्चा तो हो ही सकती है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ केन्द्र सरकार की ही करीब 950 योजनाएं चलती हैं जिस पर सकल घरेलू उत्पाद की करीब पांच फीसदी राशि खर्च होती है। इसके अलावा मध्यम वर्ग को खाद्य, रसोई गैस और उर्वरक पर सकल घरेलू उत्पाद की तीन फीसदी राशि खर्च होती है।

रोजर दुबुई की नयी पेशकश एक्सकैलिबर स्पाइडर अल्टीमेट कार्बन

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। तकनीकी एवं प्रायोगात्मक डिजाइन के क्षेत्र में अग्रणी घड़ी निर्माता कम्पनी रोजर दुबुई ने कलाप्रवीण तकनीकी के साथ अब एक्सकैलिबर स्पाइडर अल्टीमेट कार्बन की पेशकश की है, जो कि वास्तव में अपने समय से आगे की परिकल्पना है।

सही मायनों में रोजर दुबुई के इनोवेशन एवं ब्रेकिंग पांइट के लिये तकनीकी एवं सौंदर्यवादी सीमाओं को आगे बढाने का अभियान रोजर दुबुई के डीएनए का अभिन्न अंग है। इस तरह के निर्माण में रोजर दुबुई के समकक्ष कोई अन्य कम्पनी नहीं है।

विघटनकारी सामग्रियों के साथ अपने लगन के लिए प्रसिद्ध, साथ ही साथ विश्व का सर्वोत्तम उत्पादन करने की अपनी क्षमता के साथ, रोजर दुबुई ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता को साबित किया है। परिष्कृत तकनीक की अपनी महारत को दिखाते हुए, मेसन जो दुर्लभ होने का साहस करता है, ने जटिलता-चार्ज हाइपर वॉच के युग में शुरुआत करके खुद को एक महत्वाकांक्षी चुनौती दी है।

विरोधाभास इस खेल का नाम है क्योंकि एक्सकैलिबर स्पाइडर अल्टीमेट कार्बन टाइमपीस वॉच मेकिंग कोड को बाधित करते हुए अपने सीरियल इनोवेटर डीएनए के साथ ब्रांड के लिंक को बनाए रखने का प्रबंधन करता है। विरोधाभास जारी है क्योंकि अल्ट्रा-परिष्कृत प्रौद्योगिकी की लपट निगरानी के साथ घडी निर्माण इसे वजन का आभास दिलाती है।

सामग्री संयोजन की एक पेचीदा स्थिति में, यह अत्यधिक जटिल मॉडल ज्यादातर एक मामले के साथ बहु-परत कार्बन से बना होता है और इसी तरह एक कार्बन पट्टा होता है। ग्राउंडब्रेकिंग हाइपर वॉच से हटकर अंतिम चरण में, 166 डायमण्ड्स के साथ कार्बन स्ट्रैप को तैयार किया है, जो रोजर दुबई के लिए एक अपूर्व कदम है। रोजर दुबुई सिग्नेचर बन चुके अपने शाइनिंग एस्ट्रल स्केलेटन स्टार को गूँजते हुए, इस असाधारण टाइमपीस में एक विश्व-प्रथम टर्बिलोन कैरेज सेट भी शामिल है, जो बैगेट-कट हीरे के साथ सेट है, जो कुछ बहुत ही साहसी व्यक्तियों के लिए डिजाइन किए गए मॉडल के लिए अंतिम स्पर्श है।

सिडबी ने की हर साल छोटे उद्यमियों को सम्मानित करने की पहल

प्रयागराज, 11 जनवरी (ए)। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस साल से हर वर्ष छोटे उद्यमियों को सम्मानित करने की पहल की है। इस दिशा में सिडबी 12 जनवरी को नयी दिल्ली में 27 उद्यमियों को सम्मानित करेगा। यहां कुम्भ मेला क्षेत्र के सेक्टर एक में स्थित सिडबी के पंडाल में संस्था के एक अधिकारी ने बताया कि छोटे उद्यमियों की कारोबारी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। इसी को ध्यान में रखकर सिडबी ने हर वर्ष छोटे उद्यमियों को सम्मानित करने का निर्णय किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 12 जनवरी को नयी दिल्ली में 27 उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान एसएमई ऑफ दि ईयर, मोस्ट इन्नोवेटिव एसएमई, यंग एसएमई अचीवर, टेक सेवी एसएमई, बेस्ट एसएमई एक्सपोर्टर और वुमन अचीवर वर्ग के तहत दिया जाएगा। सिडबी के अधिकारी ने बताया कि सम्मानित उद्यमियों को आईआईएम लखनऊ में 10-15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उनके प्रबंधकीय कौशल को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, कई उद्यमियों के लिए बड़े कॉरपोरेट घराने मार्गदर्शक (मेंटर) बनेंगे जिसके लिए उनसे बातचीत कर ली गई है।

प्लस कंस्ट्रक्शन कैमिकल्स से बिक्री बढ़ाने का एक नया रास्ता खुलेगा: घोष

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एम पी बिड़ला ग्रुप की प्रमुख कंपनी, ने परफैक्ट प्लस सीमेंट ब्रांड के साथ ही वॉल पुट्टी और कंस्ट्रक्शन कैमिकल्स को भी लॉन्च करने की घोषणा की है। बिड़ला कॉर्पोरेशन भारत के शीर्ष सीमेंट निर्माताओं में से एक है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 15.5 मिलियन टन है।

इंडीपेंडेंट होम बिल्डर्स के साथ कारोबार को बढ़ाने के लिए, बिड़ला कॉर्पोरेशन पहली बार अपने मुख्य व्यवसाय से अलग ऐसे उत्पादों को लॉन्च कर कारोबार का विस्तार कर रहा है जो ब्रांड के सीमेंट से घर तक के वादे को पूरा करता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि घर कैसे बनते हैं, इसीलिए तो मजबूत घर के लिए सिर्फसही सीमेंट ही नहीं, सही सलाह भी चाहिए।

इन नए उत्पादों में तीन उत्पाद शामिल हैं जिनमें -परफैक्ट प्लस आईडब्ल्यूपी (इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग), परफेक्ट प्लस एसबीआर (स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर) लेटेक्स और परफैक्ट प्लस वॉल पुट्टी-लॉन्च किए गए हैं और यह लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में तुरंत उपलब्ध होगा। अगले कुछ हफ्तों में, ये उत्पाद इंदौर में उपलब्ध होंगे। परफैक्ट प्लस आईडब्ल्यूपी में अद्वितीय जल प्रतिरोधक क्षमता हैं, जबकि परफैक्ट प्लस एसबीआर लेटेक्स एक मल्टीपर्पज पॉलीमर आधारित वॉटरप्रूफिंग और मरम्मत समाधान है। इन नए उत्पादों को लॉन्च करने के मौके पर संदीप रंजन घोष, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, मार्केटिंग, आईटी और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ने कहा कि बिड़ला कॉर्पोरेशन द्वारा इन उत्पादों की शुरूआत से कंपनी और उसके सभी व्यापार साझेदारों, के लिए एक महत्वपूर्ण बिक्री बढ़ाने का एक नया रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि बिड़ला कॉर्पोरेशन के लिए हार्डवेयर और पेंट जैसे निर्माण सामग्री के खुदरा विक्रेताओं के साथ नई साझेदारी को बढ़ावा देने के अवसर भी पैदा होंगे।

कई रिसर्च के अनुसार भारत में निर्माण कैमिकल्स और एडिटिव्स की बिक्री 2025 तक लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। नए दौर के निर्माणों में विभिन्न प्रकार के कैमिकल्स और एडिटिव्स का विकास और उपयोग किया जा रहा है, और इनके लिए बाजार के हर स्तर पर व्यापक स्तर पर बढ़ने की उम्मीद है।

नियमों में बदलाव से मार्च तक बंद हो जाएंगे 50% एटीएम

जालंधर, 11 जनवरी (ए)। ए.टी.एम. के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनेजमैंट के मानकों व अपग्रेड में बदलाव के चलते देश के 50 प्रतिशत ए.टी.एम. मार्च तक बंद हो सकते हैं, कन्फैडरेशन ऑफ ए.टी.एम. इंडस्ट्री (सी.ए.टी.एम.आई.) द्वारा यह आशंका जताई जा चुकी है। आधे ए.टी.एम. बंद हो जाने से बैंकों में फिर से भीड़ बढ़ जाएगी और लोगों को पहले की तरह लाइन में लगकर पैसे निकलवाने पड़ेंगे। ए.टी.एम. बंद होने की मार नोटबंदी की तरह साबित हो सकती है। इसके चलते जहां जनसाधारण को दिक्कत उठानी पड़ेगी वहीं बैंकों पर भी काम का लोड बढ़ जाएगा।

जानकारी के मुताबिक ए.टी.एम. में कैश डालने के लिए कैसेट स्वैप मैथेड में बदलाव किया जा रहा है, इसके चलते कंपनियों द्वारा ए.टी.एम. चलाना मुश्किल हो जाएगा जिसके चलते कंपनियों को मजबूरन इन्हें बंद करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि कैश लॉजिस्टिक्स और कैसेट स्वैप के नए मैथेड पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

इसके अलावा ए.टी.एम. के लिए दूसरे मानकों में भी बदलाव किया गया है। ए.टी.एम. चलाने वाली कम्पनियों के पास इतनी बड़ी रकम खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मौजूदा समय में देश में करीब 2.38 लाख ए.टी.एम. हैं, इनके जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, यदि आधे बंद हो जाएंगे तो इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ेगा। ए.टी.एम. के बंद होने से लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी।

1 लाख ऑफ साइड, 15,000 व्हाइट लेबल: बताया जा रहा है कि ए.टी.एम. चलाने वाली कम्पनियां मार्च 2019 तक करीब 1.13 लाख ए.टी.एम. बंद करने को मजबूर हो जाएंगी। बंद होने वाले ए.टी.एम. में से करीब एक लाख ऑफ-साइड ए.टी.एम. होंगे, जबकि 15,000 से ज्यादा व्हाइट लेबल ए.टी.एम. होंगे। अधिकतर ए.टी.एम. गैर-शहरी क्षेत्र से होंगे, ये उन जगहों पर लगे हैं जहां पहले से ए.टी.एम. की काफी कमी है। ऐसे में गैर-शहरी क्षेत्र के लोगों को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर एक तरफ जहां ए.टी.एम. कम हैं वहीं बैंक भी दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं। इससे कमजोर वर्ग के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने की सरकार की कोशिशों को झटका लग सकता है, ये लोग सरकारी सबसिडी का पैसा निकालने के लिए भी ए.टी.एम. का इस्तेमाल करते हैं। सी.ए.टी.एम.आई. का कहना है कि इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि बैंक मानकों को पूरा करने पर आने वाले अतिरिक्त खर्च का बोझ उठाएं। उसने कहा है कि जब तक ए.टी.एम. चलाने वाली कम्पनियों को यह खर्च करने में बैंकों की तरफ से मदद नहीं मिलती है, तब तक बड़ी संख्या में ए.टी.एम. के बंद होने के आसार बने रहेंगे। बैंकों को यदि वर्क लोड बढऩे से बचना है तो उन्हें उक्त राशि खर्च करनी पड़ सकती है। बैंकिंग सेवा में सुधार लाने की बातें की जा रही हैं लेकिन यदि ए.टी.एम. बंद हो जाएंगे तो इसका उलटा असर पड़ेगा जिसकी मार जनता को झेलनी पड़ेगी।

रियल्टी कंपनी ग्रेनाइट गेट के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अनुमति

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने एनसीआर की रियल्टी कंपनी ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। घर खरीदारों ने शिकायत की थी कि कंपनी के पास परियोजना को पूरा करने की क्षमता नहीं है। तीन घर खरीदारों की अपील को स्वीकार करते हुए एनसीएलटी के अध्यक्ष एम एम कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी। कंपनी नोएडा में लोटस पनाचे आवासीय परियोजना तैयार कर रही है।

ग्रेनाइट गेट इस परियोजना के तहत 3,000 फ्लैटों का निर्माण कर रही है। यह परियोजना 2010 में शुरू की गई थी। यह 3सी कंपनी समूह की इकाई है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के बाद घर खरीदारों को इसके तहत वित्तीय ऋणदाताओं का दर्जा दिया गया है। बिल्डर द्वारा फ्लैटों का आवंटन करने में विफल रहने के बाद घर खरीदारों ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। बिल्डर खरीदारों का पैसा लौटाने में विफल रहा था।

रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्ती, ई-वे बिल जैनरेट करने पर लगी रोक

नई दिल्ली, 11 जनवरी (ए)। जी.एस.टी. कलैक्शन में लगातार गिरावट से चिंतित सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के मकसद से रिटर्न नहीं भरने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रिटर्न नहीं भरने वाले कारोबारियों के ई-वे बिल जैनरेट करने पर रोक लगा दी गई है और अब वे 50,000 रुपए से ज्यादा के माल की ढुलाई नहीं कर सकते।

आदेश के तहत जी.एस.टी.एन. उन सभी सप्लायर्स या रैसीपिएंट को ई-वे फाइलिंग पोर्टल पर ब्लॉक करेगा, जिन्होंने किसी भी दो टैक्स पीरियड (महीने या तिमाही) में रिटर्न नहीं भरा है। इससे अब उनके लिए माल का ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं होगा क्योंकि जी.एस.टी. कानून के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा माल की आवाजाही पर ई-वे बिल भरना अनिवार्य है। यह इंटरस्टेट और राज्य के भीतर दोनों तरह की ढुलाई पर लागू होगा।

टैक्स चोरों को पकडऩा होगा आसान: फिलहाल करीब 28 प्रतिशत लोग जी.एस.टी. रिटर्न नहीं भर रहे हैं, जबकि ई-वे बिल जैनरेशन की तादाद ज्यादा है। सरकार को आशंका है कि ऐसे लोग माल सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर वाजिब टैक्स नहीं दे रहे हैं। 20 दिसम्बर तक भरे गए नवम्बर महीने के जी.एस.टी.आर.-3बी की फाइड्क्षलग के लिए 99 लाख असैसी एलिजीबल थे लेकिन करीब 70 लाख ने ही इसे भरा। नॉन-फाइलर्स की तादाद में दिसम्बर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि ई-वे बिल पर रोक के बाद टैक्स चोरी करने वाले नॉन-फाइलर्स को पकडऩा आसान हो जाएगा।

ई-वे बिल फाइलिंग: ई-वे बिल की फाइलिंग दो चरणों में होती है। कोई माल भेजने से पहले सप्लायर और रैसीपिएंट को पार्ट-ए भरना होता है जबकि माल डिलीवर करने के बाद ट्रांसपोर्टर को पार्ट-बी भरना होता है। अधिकारियों का कहना है कि माल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पकड़े जाने के डर से कई असैसी ई-वे बिल का अनुपालन तो करते हैं लेकिन रिटर्न नहीं भरते। नॉन-फाइलर्स पर और भी कई बंदिशें लगाई जा सकती हैं जिसमें भारी पनैल्टी भी शामिल है।